Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to undertake demarcation of submergence area in Delhi-laid.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 वर्षों से लम्बित अनधिकृत कालोनियों को पास करने की समस्या का इस सदन में विधेयक लाकर स्थायी समाधान किया गया है । लम्बे समय के पश्चात आज यह कालोनियाँ पास हो गई हैं, इसके लिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ । मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले बदरपुर क्षेत्र में स्थित कालोनियाँ पास हो गई हैं, इसके लिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ । मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले बदरपुर क्षेत्र में स्थित कॉलोनियाँ भी पास हो गई हैं, परंतु वहां एक और समस्या से लोग परेशान हैं जिसके बारे में, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । दिल्ली में मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत दिल्ली में जो भूमि को अलग-अलग जोन में बांटा गया है, उनमें से 1 जोन 0 जोन कहलाता है । यह जोन यमुना के फलड-प्लेन एरिया जिसे डूब क्षेत्र कहते हैं के विषय में है । डब क्षेत्र की बाउंडी की निशानदेही या डिमार्केशन आज तक नहीं की गई है, यह कार्य राजस्व विभाग या सिंचाई विभाग जो दोनों दिल्ली सरकार के अधीन का है । इन दोनों विभागों की यह जिम्मेदारी है कि यह गत कुछ निर्धारित वर्षों में हुई वर्षा के आधार पर डूब क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करें, क्योंकि आज तक यह दोनों विभागों की डूब क्षेत्र की सीमाएं अंकित नहीं की गई हैं इसलिए उसके आस-पास स्थित कालोनियाँ जैसे मीठापुर, जैतपुर, हरिनगर इत्यादि के निवासियों को अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । वह भूमि पहले कृषि भूमि थी जिसे भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में किसानों ने विक्रय कर दी थी और उन पर आज कॉलोनियाँ बन गई हैं, जिसमें लाखों लोग निवास करते हैं, क्योंकि डूब क्षेत्र की निशानदेही या डिमार्केशन आज तक दिल्ली सरकार एवं उनके अधीन विभागों द्वारा नहीं किया गया है । इसलिए वहाँ रह रहे निवासी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । इस विषय में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भी निर्देशित किया है कि डूब क्षेत्र का डिमार्केशन किया जाए,

उपरोक्त कालोनिया डूब क्षेत्र के बाहर हैं । राजस्व विभाग के एस0डी0एम0 इसके नोडल अधिकारी होते हैं । बच्चों के वयस्क होने पर या पुत्र के विवाह पश्चात यहाँ रह रहे निवासी कुछ अतिरिक्त कमरे बनाते हैं या फिर चाहे वह घर को रेनोवेट करते हैं तो उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है ।

मेरा यह निवेदन है कि दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी है तो इसलिए माननीय लेफिटनेंट गवर्नर साहब से बात कर दिल्ली सरकार को निर्देशित किया जाए कि वह जल्दी से जल्द दिल्ली विकास प्राधिकरण के समन्वय से डूब क्षेत्र का डिमार्केशन का कार्य पूर्ण करें ।